Unrest among employees of MDL

*242. SHRI SATISHCHANDRA SITARAM PRADHAN: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether it is fact that unrest among employees of the Mazgaon Dock is increasing day by day;

(b) whether the employees have been agitating demanding cancellation of negotiations Committee; and

(c) if so, the reason for the inaction in the matter?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

The industrial relations situation in MDL have been generally peaceful for the last several years. However, since 25.11.99 Mazagon Godi Kamagar Sanghatana (MGKS), one of the several Unions in MDL, have been holding daily gate meetings of the industrial operatives on the main road outside MDL gates during the lunch hour from 1130 hrs to 1200 hrs. demanding, inter alia, election of authorised office bearers of Union by secret ballot and expressing lack of faith in the present Bargaining Council which is the forum for negotiating all industrial relations issues. This council was constituted in 1992 with the representatives of all the Unions existing at that time. MGKS formed on 1.5.97 has refused to join this Council. MGKS has given a 14 day strike notice dated 2nd December 1999 for a one day strike. The Company has clarified its stand on the issues raised in the notice of MGKS.

श्री सतीश प्रधान: सभापति महोदय, मझगांव डॉक लिमिटेड कम्पनी भारत की गौरवशाली कम्पनी है। हिन्दुस्तान के लिए इस कम्पनी ने एक से एक बढ़िया फ्रिगेटस और बहुत कुछ बनाया है। कई वर्षों पहले कम्पनी में वर्कर्स की डिमांड के लिए बहुत ऐजिटेशन हुए। इससे कामगारों में अनरेस्ट का निर्माण हो गया। कम्पनी को जो काम दिया जाता था, हिन्दुस्तान सरकार की तरफ से, उसमें कटौती की गई, बहुत सारे वर्कर्स को रिट्रेंच किया गया। उसी समय फिर समझौता होने के बाद कम्पनी में बार्गेनिंग काउंसिल का निर्माण हुआ। तब से इस बार्गेनिंग काउंसिल के साथ मेनेजमेंट बातचीत करती थी और जो कुछ वर्कर्स के प्रोब्लम्स होते थे उनको हल करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन गए तीन-चार साल से इस बार्गेनिंग काउंसिल के जो वर्कर्स हैं वह ठीक ढंग से काम नहीं संभाल रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं तथा

ठीक तरह से वर्कर्स को ट्रीट नहीं करते। इसकी वजह से वर्कर्स में, कामगारों में फिर से दोबारा अनरेस्ट का निर्माण हो गया। कामगारों की मेनेजमेंट से केवल एक ही महत्वपूर्ण मांग है कि कम्पनी के अंदर वर्कर्स को रिप्रजेंट करने के लिए यूनियन के प्रतिनिधियों का चुनाव कराया जाए। मेरा यह सवाल इसीलिए था कि कम्पनी इस चुनाव के लिए तैयार नहीं है और वह टाल-मटोल कर रही है। डिफेंस मिनिस्टर जार्ज फर्नान्डीज को, मैं जब बच्चा था तभी से जानता हूं। उनका पूरे का पूरा जो कार्यकाल है वह लेबर फील्ड में बीता है और कामगारों के क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। इसलिए वह कामगारों के दुख को अच्छे ढंग से जानते हैं। तो क्या मैं उनसे यह उम्मीद करूं कि वे कामगारों का प्रतिनिधि चुनने के लिए वहां पर चुनाव जल्दी करएंगे? आपने तो वहां विजिट भी की है, हमने भी वहां पर विजिट की है। तो मेरा प्रथम सवाल यह है कि आप वहां जल्दी चुनाव कराने के लिए क्या कर रहे हैं?

श्री जार्ज फर्नान्डीज: चुनाव कराने का काम तो मझगांव डॉक लिमिटेड कम्पनी नहीं करेगी। चीफ लेबर कमिश्नर के पास यह मामला गया था। उन्होंने रीजनल लेबर कमिश्नर के हाथों में शायद इसको सौंप दिया है। जो संबंधित विभाग है वह चुनाव कराना चाहे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। सभापति महोदय, दरअसल बात यह है कि कुछ साल पहले इस कम्पनी ने ही इस प्रकार का प्रस्ताव रखा था। लेकिन उस समय मजदूर संगठनों को यह मंजूर नहीं था।

श्री सतीश प्रधान: सर, इस बार्गेनिंग काउंसिल की तरफ से जब उनकी समस्याएं खत्म नहीं होती तो फिर कामगारों को सांसदों को मिलने की जरूरत पड़ती है। वहां उनके दो प्रमुख मुद्दे हैं। जिन 750 कामगारों को रिट्रेंच किया गया था उसमें करीबन 450 कामगारों को वापिस लिया गया। अभी थोड़े से बाकी हैं। आपने जब उनको वापिस काम दिया था तब से कम्पनी ठीक तरह से चल रही है। तो उनको वापिस लेने का मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि वहां पर वर्कर्स का रिक्रूटमेंट बैन है। रिक्रूटमेंट बैन होते हुए भी ट्रेनिंग के लिए, एप्रेंटिस-शिप करने के लिए बहुत सारे लोग लिए जाते हैं और नेशनल स्तर पर लिए जाते हैं। लेकिन कामगारों का कहना है कि उनके जो बच्चे हैं वहां उनको भी काम मिलना चाहिए, उनको भी साथ में इंटरव्यू का मौका दिया जाना चाहिए और उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व रखी जानी चाहिए। यह जो उनकी मांग है, इस विषय में आप कुछ सोचेंगे?

श्री जार्ज फर्नान्डीज: सभापति जी, मेरे हाथ में यूनियन की ओर से दिया गया स्ट्राइक का नोटिस है। उसमें जो तीन मांगें हैं वह इस प्रकार से हैं: (i) Election of authorised office bearers of the union by secret ballot (ii) Abolition of contract labour (iii) Not granting bonus to the workmen without justifiable reasons and alternatively not granting ex-gratia payment. इसमें निकाले हुए लोगों की बात नहीं है। मैं जानता हूं कि मैनेजमेंट ने यूनियन को ...(**व्यवधान**)...

श्री सतीश प्रधान: वहां पर ऐसा हो रहा है कि कांट्रेक्ट लेबर को काम दिया जाता है और कम्पनी के जो टेम्परेरी वर्कर थे, उनको निकाल दिया गया और उनको वापस नहीं लिया जा रहा

है। मेरा सवाल है कि वहां पर कांट्रेक्ट लेबर बन्द होनी चाहिए। कंपनी के पास काम है और कम्पनी वह काम अपने कामगारों से नहीं करवाती है बल्कि कांट्रेक्ट लेबर से करवाती है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज: सभापति जी, यह जो कांट्रेक्ट लेबर की बात कही है, मझगांव डॉक अनेक युद्ध के जहाजों को बनाती है और उसमें ऐसे कई काम होते हैं जिनको मझगांव डॉक स्वयं अपनी तरफ से नहीं करती है। कुछ ऐसे काम हैं जिनको कांट्रेक्ट पर दिया जाता है और वह कांट्रेक्टर उस काम के लिए वहां कुछ कांट्रेक्ट लेबर रखता है। उस स्थान पर भीतरी लोगों को काम पर लगाना कठिन है। मगर माननीय सदस्य का जो सुझाव है उस पर हम विचार कर लेंगे।

MISS SAROJ KHAPARDE: Sir, I have gone through the reply given by the Minister very carefully. On the basis of the reply I ask: Would the hon. Minister explain it giving little more details as to what he means by saying, 'industrial relations situation in MDL have been generally peaceful over the last several years'? It has further been said in the reply that the company has clarified its stand on the issues raised in the notice to NGKs. May I know from the hon. Minister as to what were the issues raised and what has been the clarification given by the company in this regard?

श्री जार्ज फर्नान्डीज: सभापति जी, प्रस्तावित विषयों के बारे में मैंने अभी बता दिया है, हड़ताल के नोटिस को पढ़कर सुना दिया है, उसमें यही कहा है कि:— (i) Election of authorised office bearers of the union by secret ballot (ii) Abolition of contract labour

(iii) Not granting bonus to the workmen without justifiable reasons and alternatively not granting ex-gratia payment. अब इसमें पहले और दूसरे के बारे में हमने बता दिया है और तीसरा कारण बोनस नहीं देने का है। ...(**व्यवधान**)...

कुमारी सरोज खापर्डे: अपने जवाब में मंत्री जी आपने यह कहा है—Situation in MDL has been peaceful over the last several years.

श्री जार्ज फर्नान्डीज: उस पर मैं आ रहा हूं। आपका यह जो प्रश्न है कि क्या खुलासा उनको भेज दिया है, यूनियन को बातें बता दी हैं तो यह जो तीन बातें उनकी हैं, उनकी हकीकत के बारे में उनको बता दिया गया है और आज वहां पर इन चीजों पर बातचीत हो रही है। यूनियन को कहा गया है कि इस पर बातचीत हो जाए तो अच्छा है। वह बातचीत हो रही है। वहां पर शांतिमय ढंग से हर प्रकार का काम चल रहा है। वहां पर पिछले कई साल में दो बार कुछ विवादों के कारण काम बन्द हुआ था। एक बार जब एक यूनियन के अध्यक्ष डा० दत्ता सामंत की हत्या हो गई थी तब वहां पर दो दिन के लिए समूचा काम बंद रहा और उसके पहले एक बार किसी सरकारी निर्णय को लेकर कुछ विवाद हुआ था ...(**व्यवधान**)...

कुमारी सरोज खापर्डे: किस विवाद को लेकर बंद हुआ था उसके बारे में विस्तार से बताइये।

श्री जार्ज फर्नान्डीज: सभापति जी, इम्पलाइज पैंशन स्कीम को लेकर विवाद हुआ था और उसके कारण एक दिन काम बंद हुआ था। यह 1995 की बात है।

SHRI JAYANT MALHOUTRA: As the hon. Minister knows since he has been a part of the labour movement of Bombay and I also know because I have been on the other side for a long time in Bombay and Maharashtra, most of these labour problems arise when their is shortage of work. I had visited with the other Members of the Public Accounts Committee the Mazgaon Dock as well as some other establishments. It is our opinion that there was practially no work given to the Mazgaon Dock despite the fact that very expensive facilities had been created for submarine construction, etc. I would like to have the reaction of the hon. Minister on this because I raised this issue earlier also and requested that there should be a Short Duration Discussion on this whole policy of defence procurements, but so far we have not had a positive response from the hon. Minister.

श्री जार्ज फर्नान्डीज: सभापति जी, इस मझगांव डॉक में जो काम हो रहा है, वह हमारी नौसेना की जो आवश्यकताएं हैं, उसी की पूर्ति करता है। कुछ बाहरी काम भी कभी-कभी आ जाता है और हम लोगों का कितना काम हो सकता है, यह हर साल के बजट में क्या इंतज़ामी होती है, उस पर निर्भर करता है और उसके साथ-साथ आवश्यकताओं पर भी निर्भर करता है। मगर मुख्यतः आवश्यकताएं जो भी हों, उस पूंजी के आबंटन के बाद ही तो वहां काम की बात हो सकती है इसलिए इस पर कोई भी एक ठोस कार्यक्रम बनाना कि इतना काम वहां पर होगा ही, यह तय करना संभव नहीं है। हमारा प्रयास तो होता है कि अगर कुछ बाहरी काम भी मिल सके तो उसको लें, केवल मझगांव डॉक के लिए ही नहीं बल्कि हमारे मंत्रालय के अंतर्गत इस प्रकार के जो अन्य डॉकयार्ड हैं, उनके लिए भी।

MR. CHAIRMAN: Shrimati Kamla Sinha ...*(Interruptions)*...

SHRI JAYANT MALHOUTRA: Sir, I am not satisfied with the answer. We are already procuring submarines and other vessels from all over the world. The facilities which have been created in India at Mazgaon Dock and other places are lying absolutely idle because there is no work. Despite numerous queries to this effect, no positive or clear answer has been given by the Ministry of Defence.

MR. CHAIRMAN: Shrimati Kamla Sinha ...*(Interruptions)*...

SHRI JAYANT MALHOUTRA: I would like the Minister to respond to this because it is a very important question. ...*(Interruptions)*...

SHRI GEORGE FERNANDES: Sir, I have already responded to his query. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI KAMLA SINHA: Sir, if we go by the nature of this question, then it should be addressed to the Labour Ministry. Anyway, since the Mazgaon Dock does work for the Defence Ministry, the second part of the question is very relevant. Sir, Mazgaon Dock was created to meet the defence requirements of our Navy. Now, my question is a corollary to what the previous speaker ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: It is all right. Put your question. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI KAMLA SINHA: Sir, I also visited the Mazgaon Dock and saw. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Put your question.

SHRIMATI KAMLA SINHA: Sir, I would like to say that the Mazgaon Dock can be made useful for our Navy if enough money is provided to build new naval vessels. For example, it can build submarines and other naval vessels. Why is the Government not providing enough money to the Mazgaon Dock?

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज: जितना संभव है उतना काम वहां पर हो रहा है और उसको बढ़ाने के जो भी तौर-तरीके हैं, उनको अपनाने के लिए हम तैयार हैं।

Conversion of losses of Singareni collieries into equity

*243. SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Will the Minister of MINES AND MINERALS be pleased to state:

(a) whether Andhra Pradesh Government has requested for conversion of losses of Singareni Collieries Company Limited into equity;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether it is a fact that the issue has been pending for clearance before the Union Government for several years; and